



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 18 अगस्त, 2000/27 भाद्रपद, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 18 अगस्त, 2000

संख्या 1-54/2000-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम, 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2000

(2000 का विधेयक संख्यांक 18) जो आज दिनांक 18 अगस्त, 2000 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

अजय भण्डारी,
सचिव।

2000 का विधेयक संख्यांक 18

हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2000

(विधान सभा में पुनः स्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1968 (1968 का 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्न-लिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2000 है।

संक्षिप्त
नाम।

1968 का
12

2. हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1968 की धारा 3 में,—

धारा 3 का
संशोधन।

(क) उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(2) उप-धारा (1) और अधिनियम में टिकट से प्रवेश के सम्बन्ध में अंतर्विष्ट अन्य उपबन्धों या अन्यथा अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार किसी भी वर्ग के मनोरंजन पर, उप-धारा (1) के अधीन प्रभार्य शुल्क के बदले में, विहित रीति में एक मूख्य मनोरंजन शुल्क स्वीकार (प्रतिगृहीत) कर सकेगी और उसे साठ व्यक्तियों तक की सीटों की क्षमता वाले किसी वीडियो प्रदर्शन के स्वत्वधारी से भिन्न स्वत्वधारी से प्रतिमास अग्रिम में वसूल कर सकेगी।

परन्तु साठ व्यक्तियों तक की सीटों की क्षमता वाले किसी वीडियो प्रदर्शन पर, संदाय पर प्रदर्शन करने वाला, स्वत्वधारी, मनोरंजन शुल्क का अग्रिम में तीस हजार रुपये प्रतिमास से अनधिक दर पर, विहित रीति में, जो सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जा सकेगी, संदाय करेगा।”;

(ख) उप-धारा (2-क) का लोप किया जाएगा; और

(ग) उप-धारा (3) में चिन्ह, कोष्ठकों, अकों और शब्दों, “(2) और (2-क)” के स्थान पर “और (2)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1968 की धारा 3 के अधीन सरकार, दूरदर्शन के माध्यम से उपलब्ध करवाए गए से भिन्न सभी मनोरंजनों को बाबत वास्तविक आधार पर सदैव मनोरंजन शुल्क के बदले में एक मुश्त मनोरंजन शुल्क को विहित करने में सक्षम है। दूरदर्शन प्रदर्शन सहित मनोरंजन को सभी श्रेणियों के लिए समरूप उपबन्ध बनाने के लिए इन उपबन्धों को उपयुक्त रूप में संशोधित किए जाने का विनिश्चय किया गया है।

2. यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रद्योण शर्मा,
प्रभारी मंत्री।

शिमला:

तारीख.....2000.

विस्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 अधिनियम के अधीन उद्गृहीत मनोरंजन शुल्क के बदले में एक मुश्त वसूली का उपबन्ध करता है। विधेयक किसी नए कर या किसी विधायन कर को कम करने का प्रस्ताव नहीं करता है। विधेयक के उपबन्ध, अधिनियमित होने पर, विद्यमान प्रशासनिक तंत्र द्वारा प्रशासित होंगे।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 सरकार को अधिनियम के अधीन उद्गृहीत मनोरंजन शुल्क के बदले में एक मुश्त स्वीकार करने के लिए नियम बनाने को सक्षम करता है। यह प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 18 of 2000.

THE HIMACHAL PRADESH ENTERTAINMENTS DUTY
(AMENDMENT) BILL, 2000

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Entertainments Duty Act, 1968 (Act No. 12 of 1968).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Entertainments Duty (Amendment) Act, 2000.

Short title.

2. In the Himachal Pradesh Entertainments Duty Act, 1968 in section 3,—

Amendment of section 3.

(a) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) and other provisions in relation to admission by tickets or otherwise contained in the Act, the Government may accept, in the prescribed manner, lumpsum entertainment duty for any class of entertainment in lieu of the duty chargeable under sub-section (1) and recover the same in advance per month from the proprietor other than the proprietor of a video exhibition having seating capacity upto sixty persons :

Provided that the proprietor of a video exhibition, exhibiting shows on payment and having seating capacity upto sixty persons, shall pay entertainment duty in advance and at a rate not exceeding rupees 30,000 per month as may, in the manner prescribed, be specified by the Government from time to time.”;

(b) sub-section (2-A) shall be omitted ; and

(c) in sub-section (3), for the sign, brackets, figures and word “, (2) and (2-A)”, the word, brackets and figure “and (2)” shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under section 3 of the Himachal Pradesh Entertainments Duty Act, 1968, the Government is empowered to prescribe lumpsum entertainment duty in lieu of that payable on actual basis in respect of all entertainments other than those provided through a television exhibition. In order to make similar provisions for lumpsum entertainment duty for all classes of entertainments including television exhibition it has been decided to amend these provisions suitably.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PRAVEEN SHARMA,
Minister-in-Charge.

SHIMLA :
Dated....., 2000.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of the Bill provides for recovery of lumpsum in lieu of entertainments duty levied under the Act. The Bill does not propose to levy any fresh tax or to reduce any existing taxes. The provisions of the Bill when enacted will be administered by the existing administrative machinery and will not result in additional expenditure from the State exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill empowers the Government to make rules for accepting lumpsum in lieu of the entertainment duty levied under the Act. This delegation is essential and normal in character.